



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजित करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शनिवार 28 मार्च 2020 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 177

महत्वपूर्ण एवं खास

स्नातकोत्तर और पीएचडी दाखिले की अंतिम तिथि 20 अप्रैल तक बढ़ी

नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईटी) ने कोरोना महामारी को देखते हुए स्नातकोत्तर और पीएचडी के दाखिले के लिए अंतिम तारीख 20 अप्रैल कर दी है। आईआईटी प्रशासन ने ट्वीट कर कहा कि कोई उम्मीदवार 20 अप्रैल तक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकता है। वर्ष 2040-2021 के लिए पहला सेमेस्टर सितंबर में शुरू होना है। आईआईटी ने कोरोना को देखते हुए अपनी एकेडमिक गतिविधियां पहले से बन्द कर दी हैं।

देश में कोरोना से 17 लोगों की मौत, अभी भी 700 पीड़ित

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस भारत में अपना पैर पसारता ही जा रही है। शुरूआत सुबह तक देश में कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या 700 के करीब पहुंच गई है और 17 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया है, उसका आज तीसरा दिन है। लॉकडाउन के चलते आम जनमानस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और हजारों मजदूर अपने घरों के लिए पैदल जा रहे हैं। दुनियाभर में कहर बरपाने वाले कोरोना वायरस ने भारत में सभी को घरों में कैद करके रख दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, गुरुवार को देश में सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए सिर्फ एक दिन में करीब 80 मरीज सामने आए हैं।

पीएम ने सतीश गुजराल के निधन पर शोक व्यक्त किया

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतीश गुजराल के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा, सतीश गुजराल जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी रचनात्मकता और संकल्प के सहारे विपत्तियों पर विजय प्राप्त की। इसके लिए उनका सम्मान किया जाता था। उनकी बौद्धिक लालसा उन्हें दूर-दूर तक ले गई लेकिन वे हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। उनके निधन से दुःखी हूँ। ओम शांति।

वडोदरा के नये प्रशिक्षण संस्थान को पृथक केन्द्र में

इस्तेमाल करने की पेशकश

नई दिल्ली (आरएनएस)। रेलवे ने गुजरात के वडोदरा में मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल परियोजना के प्रशिक्षण संस्थान के नये हॉस्टल भवन को ज़रूरत पड़ने पर पृथक केन्द्र के रूप में इस्तेमाल करने के लिये चिन्हित किया है। रेलवे ने बुधवार को यह जानकारी दी। रेलवे अपनी उत्पादन इकाइयों में ज़रूरी चिकित्सा सामग्रियों के निर्माण पर भी विचार कर रहा है। इसके अलावा वह कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में केन्द्र सरकार का हाथ बंटाने के लिये और रास्ते भी तलाश रहा है। नये रेलवे प्रशिक्षण संस्थान में 168 कमरे, 334 बिस्तर और 12 बड़े कमरे हैं।

एसजेवीएन वेंटीलेटर खरीदने देगा एक करोड़

नई दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनीरख पीएसयू, एसजेवीएन लिमिटेड ने कोरोनावायरस (कोविड-19) महामारी से निपटने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इस बीमारी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। संकट की इस घड़ी में, केन्द्रीय पीएसयू कोरोनावायरस से निपटने के लिए 1 करोड़ रुपये प्रदान करने पर सिद्धांत रूप सहमत हो गया है। एसजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) नन्द लाल शर्मा ने बताया कि इस राशि का इस्तेमाल इंडिया गांधी मेडिकल हॉस्पिटल, शिमला में छह वेंटीलेटर खरीदने के लिए और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा में चार वेंटीलेटर और खनेरी स्थित रामपुर अस्पताल में कुछ वेंटीलेटर खरीदने के लिए किया।

चार लाख लोगों को खाना खिलाएगी दिल्ली सरकार

» कोरोना से जंग के लिए बना खास प्लान

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस को दिल्ली में फैलने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने विशेष योजना बनाई है। सीएम केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों के इलाज, बीमारी की रोकथाम और लॉकडाउन के मद्देनजर दिल्ली में रह रहे लोगों के खाने-पिने का पूरा इंतजाम किया है। सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली के रैनबसेरों में अभी तक 20 हजार लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, आज से इसकी संख्या 10 गुना बढ़ाकर 2 लाख की जाएगी। सरकार की योजना है कि कल से दिल्ली के 4 लाख लोगों



को खाना खिलाया जाएगा। 100 केंस रोज आएं तो दिल्ली सरकार इसे संभालने के लिए तैयार है। हमने डॉक्टरों के साथ मिलकर टीम बनाई है, जो हमें गाइड कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सरकार इस बात की तैयारी कर रही है कि अगर कोरोना से संक्रमित 500 या एक हजार मरीज भी रोज आने लें, तो

इसके लिए क्या इंतजाम है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक संभव हो सके, इलाज में कोई कमी न रहे। सीएम ने कहा कि कोरोना का खतरा देखते हुए दिल्ली सरकार ने रैनबसेरों में लोगों के रहने का इंतजाम किया है। 20 हजार लोगों को इन रैनबसेरों में खाना खिलाया जा रहा है। आज से इन रैनबसेरों में 2 लाख लोगों को खाना खिलाया जाएगा। शनिवार से इस संख्या को और बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार 4 लाख लोगों को खाना खिलाएगी। इसके अलावा आज से दिल्ली के 325 स्कूलों में लंच और डिनर देने का इंतजाम किया गया है।

» कुछ दिन पहले ही हज से लौटे थे 4 सदस्य

कोल्हापुर में एक ही परिवार के 12 लोग कोरोना से संक्रमित

मुंबई (आरएनएस)। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। यहां अब तक 130 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि कोल्हापुर में एक अनेखा मामला सामने आया है। यहां के एक ही परिवार के 12 लोग कोविड-19 वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। पता चला है कि इन्हें यह संक्रमण घर के उन चार सदस्यों से मिला, जो हज करने गए थे। वहां से लौटने के बाद उनसे परिवार के अन्य सदस्यों को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया है। जानकारी के मुताबिक सांगली जिले के इस्लामपुर गांव का रहने वाले इस परिवार के 4 सदस्य हज से लौटे थे। लौटने पर परिवार के 4 सदस्यों को अलग-थलग में रखा गया। जांच के बाद 23 मार्च को इन सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 25 मार्च को परिवार के 5 और सदस्यों

का जांच कराया गया। ये पांचों भी पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद परिवार के 3 और लोगों को बुलाया गया, जो पॉजिटिव निकले। इस तरह से एक ही परिवार के 12 लोग खतरनाक कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। इस बीच सांगली जिले के सिविल सर्जन संजय सालुनखे ने कहा कि परिवार के सम्पर्क में आने वाले सभी लोगों के सैपल अब लिए जा रहे हैं। इन सबकी रिपोर्ट आज आ जाएगी। डॉक्टरों को इस बात का डर है कि कोरोना की ये चेन काफी लंबी हो सकती है। यानी इस गांव के कई लोग इसकी चपेट में आ गए होंगे। इसके अलावा डॉक्टरों ने परिवार के सारे करीबी रिश्तेदारों को भी अलग-थलग कर दिया गया है। गौरतलब है कि अब तक देश में संक्रमित लोगों की संख्या 700 के पार हो चुकी है।

वाहनों के पंजीकरण के लिए मोबाइल नम्बर देना होगा

नई दिल्ली (आरएनएस)। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के पंजीकरण से संबंधित किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है। नियमों के तहत फॉर्म संख्या 20, 23ए, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 44 में संशोधन करते हुए इस महीने की 16 तारीख को जीएसआर संख्या 178 ई अधिसूचित की है। ये फॉर्म मोटर वाहनों से संबंधित विभिन्न स्थितियों जैसे- पंजीकरण, स्थानांतरण, वाहनों का रजिस्टर, नवीनीकरण, ड्यूलिकेट कॉपी, एनओसी प्रदान करना, पता बदलना, प्रवेश या किराया/खरीद/उपप्राधीयन लिए सीमा प्रविष्टि आदि से जुड़े हैं।

राष्ट्रपति कोविंद ने देश के सभी राज्यों पर किये जा रहे कोरोना से बचाव कार्य को सराहा

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कोरोना वायरस को देखते हुए उपराष्ट्रपति वैकेया नायडू, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने इससे लड़ने में जुटे स्वास्थ्य पेशेवरों तथा अन्य सभी के प्रयासों को सराहना की। यह जानकारी राष्ट्रपति भवन ने दी। बता दें, देश के अलग-अलग राज्यों में कोरोना वायरस की वजह से कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही हैं। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उपराज्यपाल के जरिए ही पूरा प्रशासन

काम कर रहा है। देश में कोरोना वायरस 'कोविड-19' के संक्रमण से अब तक 17 राज्यों की मौत हो चुकी है जबकि संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 727 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस का प्रकोप देश के 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैल चुका है और इसके 727 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें 677 भारतीय तथा 47 विदेशी हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से देशभर में अब तक 17 लोगों की मौत हुई है जबकि 67 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अभी तक सबसे अधिक संक्रमण के मामले सामने आए हैं।



गरीबों को मोदी कित बांटेगी भाजपा

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस ने लोगों को पूरी तरह से बेबस और लाचार कर दिया है। कोरोना संकट में कई ऐसे लोग हैं जो ज़रूरत के सामनों के लिए तरस रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी भी संकट के इस समय में ज़रूरत मंद लोगों की सहायता के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। भाजपा ने तय किया है कि भाजपा की ओर से मोदी कित के नाम से ज़रूरत मंद लोगों तक सामान पहुंचाया जाएगा। गरीब लोगों को लॉकडाउन के दौरान बांटे जाने वाले इस कित में चावल, दाल, बिस्किट, तेल और साबुन जैसे ज़रूरी सामान होंगे। इस बावत भाजपा हाई कमान ने सभी प्रदेश इकाई को कहा है कि इस तरह के कित बनाकर सभी ज़रूरत मंदों तक पहुंचाए जाएं। गुरुवार को ही महाभोज अभियान शुरू किया, जिसके तहत भाजपा की ओर से पार्टी के एक करोड़ कार्यकर्ताओं को पांच ज़रूरत मंद लोगों को प्रतिदिन भोजन कराने को कहा गया था।

130 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए लॉकडाउन आवश्यक:गोयल

नई दिल्ली (आरएनएस)। रेल तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुरूआत को देश भर के विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के प्रतिनिधियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ताकि देश में कोविड-19 के प्रभाव और लॉकडाउन का आकलन किया जा सके, और स्थितियों को सुधारने के बारे में उनकी प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त किए जा सकें। बैठक में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वाणिज्य सचिव डॉ. अनूप वाधवन्, विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक अमित यादव भी उपस्थित थे। बैठक में निर्यात संवर्धन परिषदों की गतिविधियों और व्यवसायों पर महामारी के प्रभाव और साथ ही

इन कठिनाइयों से निबटने के लिए कई सारे सुझावों पर चर्चा की गई। पीयूष गोयल ने बैठक में कहा कि निर्यात-आयात देश की गतिविधियों में से है, लेकिन इसके साथ ही, 130 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए लॉकडाउन भी आवश्यक था। ऐसे में एक संतुलन बनाए रखने के साथ ही कठिनाइयों को कम करने के लिए समाधान खोजना भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार समय से काफी आगे चल रही है। वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा हाल ही में की गई घोषणाओं में इसे देखा जा सकता है। कठिन समय में, व्यक्ति दूसरों के अनुभवों से सीख लेकर भविष्य की योजना बना सकता है। गोयल ने कहा कि सम्मेलन में दिए गए सुझावों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्यात और आयात संगठनों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी उचित मांगों के साथ सामायोजन करने का प्रयास करेगी, और व्यावहारिक परिणामों के साथ सामने आएगी। बैठक में फियो, ईपीसी, एसआरटीईपीसी, जीजेईपीसी, सीएलई, सीईपीसी, शेफेक्सल, फार्माटैक्सल, इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर, सेवाओं, रेशम उद्योग, परियोजनाओं, टेक्सटाइल, ऊन, प्लास्टिक, केमिकल्स तथा खेल सामग्रियों के निर्यात से जुड़े संगठनों ने हिस्सा लिया।

एनडीआरएफ के तहत 8 राज्यों को 5,751.27 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को मिली मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने उन आठ राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) के तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने को मंजूरी दी है, जो वर्ष 2019 के दौरान बाढ़/भूस्खलन/चक्रवाती तूफान/सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। एचएलसी ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से आठ राज्यों को 5751.27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने को मंजूरी दी है। हालांकि, इसके तहत वित्त वर्ष की 1

अप्रैल को एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 50% का समायोजन करना होगा। इन आठ राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मिलेगी - बिहार को 953.17 करोड़ रुपये (इनमें से 400 करोड़ रुपये पहले ही 'खाता आधार पर' जारी किए जा चुके हैं), केरल को 460.77 करोड़ रुपये, नगालैंड को 177.37 करोड़ रुपये, ओडिशा को 179.64 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 1758.18 करोड़ रुपये, राजस्थान को 1119.98 करोड़ रुपये एवं पश्चिम बंगाल को

1090.68 करोड़ रुपये दिए जाएंगे इन राज्यों को यह धनराशि वर्ष 2019 के दौरान आई बाढ़/भूस्खलन/चक्रवाती तूफान, सूखा (खरीफ) के लिए दी जाएगी। उधर, कर्नाटक को 2018-19 के सूखे (रबी) के लिए पशुपालन क्षेत्र के तहत 11.48 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी। वर्ष 2019-20 के दौरान अब तक केंद्र सरकार पहले ही 29 राज्यों को 10937.62 करोड़ रुपये केन्द्रीय हिस्से के रूप में राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से जारी कर चुकी है।

लॉकडाउन' के दौरान डाक सुविधा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं डाकघर

नई दिल्ली (आरएनएस)। 'कोविड-19' को फैलने से रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान भी डाकघर बुनियादी डाक और वित्तीय सेवाएं निरंतर प्रदान कर रहे हैं। डाकघरों के सुदृढ़ नेटवर्क के माध्यम से आवश्यक आइटमों या चीजों के वितरण को प्राथमिकता दी जा रही है। डाकघर बचत बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के तहत निकासी और जमा की सुविधा भी उपलब्ध है। एटीएम सुविधा और ईपीएस

('आधार' सक्षम भुगतान प्रणाली) किसी भी बैंक के खातों से नकदी की निकासी के लिए डाकघरों में उपलब्ध कराई जाती है। डाक विभाग यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला (एसएलई चैन) में समस्त सुरक्षा उपायों को लागू करते हुए आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएं, ताकि उसके कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ-साथ नागरिकों को भी सेवाओं की सुरक्षित डिलीवरी हो सके।

राज्यपालों/ उपराज्यपालों की भूमिका महत्वपूर्ण कोरोना के विरुद्ध वृहत्तर सामुदायिक अभियान जरूरी:नायडू

नई दिल्ली (आरएनएस)। उपराष्ट्रपति एम वैकेया नायडू ने शुरूआत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न प्रदेशों/ केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों/ उप राज्यपालों से बात की तथा उनके प्रदेशों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लिए जा रहे प्रयासों के बारे में चर्चा की। वे आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यपालों/ उप राज्यपालों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज विश्व, हाल

के दशकों की संभवतः सबसे विकट स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। भारत ने इस चुनौती को पूरी गंभीरता से लिया है। उपराष्ट्रपति ने केंद्र और प्रदेश सरकारों के प्रयासों की चर्चा करते हुए टीम इंडिया की भावना को सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं कोविड 19 संक्रमण के विरुद्ध इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इस संदर्भ में उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह को याद दिलाई कि यदि आप घर

से बाहर जाएं, तो कोरोना घर में आएगा। देश भर में पूर्ण बंदी लागू कर दी गई है तथा सामाजिक व्यवहार में दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। स्थानीय स्तर पर नागरिक इन प्रयासों में सहयोग भी दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जन जागृति फैलाने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि आवश्यक है कि प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके

लिए जनता से निरंतर संवाद करना, उन्हें आधिकारिक सूचना उपलब्ध कराना ज़रूरी होगा। उन्होंने कहा कि इस चुनौती का सामना करने के लिए वृहत्तर सामुदायिक अभियान चलाने की आवश्यकता होगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य प्रशासन, सभी इलाकों में दूध, फल, सब्जी जैसे रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। उन्होंने राज्यपालों/ उप राज्यपालों से कहा कि अपने प्रदेशों में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

'पढ़ाई नहीं रुकेगी' अभियान शुरू

» ग्रेडअप की पहल
नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले प्लेटफार्म ग्रेडअप ने कोरोना वायरस के कारण 21 दिवसीय राष्ट्र व्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर 'पढ़ाई नहीं रुकेगी' अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों की विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो जेईई और नीट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।